

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई विल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1991/चैत्र 6, 1913 No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1991/CHAITRA 6, 1913

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

स्रधिसूचना

नई दिल्लों, 27 मार्च, 1991

सा. का. नि. 192 (ऋ) :--- राष्ट्रपति हारा किया गया तिस्तालेखि । ऋदिश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता :---"स. आ . 146"

संविधान (ाजस्व निष्णा) यादेण, 1991

्राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों क. प्रयोग क.ते हुण, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विवार करने के पःच.त् निम्न-लिखिल आदेश करते हैं, अर्थात्ः—

- 1. इत श्रादेश वा संक्षिण्य नाम संविधान (राजस्व वितरण) श्रादेश, 1991 है।
- ्र. सावा ण वड अविनितम,1897 (1897 क. 10) इस अविश के निर्वचन के लिए उसी प्रका: लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू हीत. है।
 - 3 (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उनबंधा के अनुसार 1 अप्रैल, 1990 को प्रारंभ होने वाले विक्तीय वर्ष में ---
 - (क) नीचे दी गई सारणी के स्तंम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के सामने राजस्वों में सहा ता अनुदा: के रूप में, उजन सारणी के स्तंभ (2) से (11) में िनर्दिष्ट राशियां जो ंन संभां में उनित्या सेक्टरों और सेशियां के रिकान संबंध सार को छंचा उठाने के लिए प्रीर 'विशेष समस्याप्रों" से संबंधित कार्यकरों पर राजस्व और पूंजा की प्रकृति के व्यन के लिए है, भारत की संचित निश्चि ५र भारित होंगी:---

परन्तु ऊपर विनिदिष् ाशियां, ऊपर विनिदिष्ट ग्रीर केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदिन सेक्टां श्रोर सेवार्यों के प्रशासांबंधी स्ताः को ऊंसा एठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यकरों पर व्यय की जाएंगः • सारणी

राष्य	निम्मलिखित से संबंधित स्तर को उंचा उठाने के लिए												
	पुलिस	शिका	<u>गेल</u>	जनजानि व	ं ग्रस्था	न्यायिकः	जिला ग्रीर राजस्व	खजानामीर लेखा	प्रणिश्चग	विशेष समस्याएं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(e)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
									(क्षए लास	 प्रोंमें)			
मान्द्र प्रदेश	2.46	162.02	14.82	16.35	110.49	56.83	11.94	7.93	17.21	831.58			
गोवा	5.41	3,45				1.52	8.09	1.88		11.25			
हरि याणा										640.11			
् हिमाचल प्रदेश		5.19	0.14	0.20	0.81	0.41	2.55	0.49	1.78	40.02			
केरल	10.16		5.22	1.13		9.86		, 					
मध्य प्रदेश	22,09		25.10	81.60	17.71		11.27	0.88	3.53	290.02			
महाराष्ट्र										770.5			
मणिपुर	11.83	82. 5		9.85	1.99	1.58	9.46		2.79	9.30			
बेचा लय	12.04				3. 6 7	_	_	~-	Ç. 20				
मिजोरम	25.00	3.75		15.05	7.06	1.00				87.5			
माधारीयः			107.85		2.43	1.65	7.31	2,43	4.70	375.0			
उड़ी सा	93.07		rained.	17.55		1.17	15.26	1.16					
पंचाब			·						- - -	1442.3			
राजस्यान	103.06		97.59		1 7,0 9	52.50	48.7	4. 2.46		158.7			
सिविकम	3.11		0.28						0.20	17.7			
क्रिपुरा	43.07	54.17	1,00	1.20	9.70		1.78		1.16				
क्तर प्रदेश	181.0	g	2.11	0.45	51.80	70.58	40.87	17,70	27.72	3848.2			
विषयमी वैणान										1225,0			

[्]यान्तु यह भौर कि किसी प्रशासन के संध्य में ऊर िनिर्दिष्ट नेनुदार की रकम, 1 अप्रैल, 1991 ो प्रारंभ होने वाले विक्तीय वर्ष के भीतर, जैसा उर वर्ष के लेकाों में प्रकट किया गया है, ऐर प्रणानन संबंधा अनुतोदिक कार्यकर या कार्यक्रमतं पर उपगत वास्त्रशिक व्यय के विक्**द्ध** समायोजन वेश व्यक्षीन है

रहा≒'णी

सञ्ब ु	निरूनिकिं ^ह ें से संबं धित स्तर को अं घा उठाने के लि <i>ं</i> !												
	पुलि	शिक्षा]	जैल ज	रजाति	स्वात्क्य]	न्यायि ः	जिला मीर राजस्व	ख्यानः प्रौंट लेखा	≖====================================	विशेष समस्याएं			
(1)	(2)	(:)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
									(रुपए लाख	 गॅमें)			
भरणाचल प्रवेश	77.88	7:22			28.99			8.28					
अस म [ु]				91.06	1.57	21.53	4.53	13,05	_ _	100.00			
- , गोबा		8.61	_		10.82	10.53	2.56			-			
केरल	49.38		11.91	1.44	4.25	23.20	5.80	0.76					
मुक्त्य प्रदेश	59.12		659.64	122.05	5.41	0.21	7.52	0.60		3.48			

⁽ख) नीचे दी ाईसार नी के संभ (1)में वितिदिस्ट प्रश्नेक राज्य के सामने राजस्त्रों में सहायता माधान के धूँकम में हींउसता सारणी के धूँस्तंभ (-2)से (11) में निर्मिटिस्ट राशियां, जो उत संभों में विणित स्तर को ऊंचा उठाने योंग 'शियोग समस्याओं' के लिए कैंखीय सरकार नारा मन्मोदित कार्यकर्मों पर 1 अप्रैल, 1990 से प्रारंभ होने जाता त्नीय वर्ष में उपगत राजस्य औं पत्री की प्रकृति के व्यय के लिए हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होगी:──

1	2	3	4	5	в	7	8	9	10	11
भेषालय	31.81	23.09				2.60	1,24			
मि जोरम		***					_	4.80		
नागालैण्ड			- <u>-</u>			0.07				
उड़ीसा		221.80	_	54.58	0.2		1.44			
राजस् यान	12.50		16.29	7.83	12.52	1.86	7.01	1.00	5.94	56.99
सि विध म	0.21	→ →		1.09	0.76		(-)0.34			
बि पुरा	20.91	2.85		1.50	C. 57		0.39	0.98	9.29	~-
उत्तर प्रवेश	90.48		114.90	1.50	21.84	4.15	41.60	17.59		
पश्चिम ग्रंगाल	609.58	184.76	108.15	99.26	46.66	12.53	7.11	10.50	20,00	 -

परन्तु यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तियिक व्यय, जैसा कि उन वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया।
गया है, जस प्रशासन के साधने उत्पर विनिदिष्ट अनुवान की किसी सेकम है, तो इस प्रकार अनिरिक्त संदत्त की गई रकम ऐसी [किसी राणि या
राणियों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संवेध ो जाए।

(2) 1 भन्नैल, 1990 को प्रारंभ होने वाले विक्तीय वर्ष में किसी राज्य को उपपैरा (1) के खंड (भ) भीर (ख) के श्रवीन संदेय कोई राशि का राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) मं. 3 श्रावेश, 1990 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के श्रनुसरण में उस विक्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशिय सा राशियों के भन्तिरिक्त होंगी।

> आर. वेंकटरामन, राष्ट्रपति

[कां. सं. 19 (2)/91- **एस.-1**]

के. एस. मोहनपुरिया, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1991

G.S.R. 192(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 146"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1991

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

- 1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1991.
- 2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
- 3. (1) In accordance with the provisions of claus: (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1990, as grants-in-aid of the revenues of—
 - (a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (11) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature on programmes for upgradation of standards and "Special Problems" relating to the administration of the sectors and services mentioned in these columns:—

TABLE

	For upgradation of standards relating to										
State	Police	Education	Jail	Tribal	Health	Judicial	District and Revenue	Treasury and Accounts	Training	Special Problem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					(Rupees	in lakhs)					
Andhra Pradesh	2.46	162.02	14.82	16.35	110.49	56.83	11.94	3.93	17.21	831.58	
Goa	5.41	3.45		1.1	4.1	1.52	8.09	1.88		14,25	
Haryana										646.11	
Himachal Pradesh		5,19	0.14	0.20	0.81	0.41	2.55	0.49	1.78	46.02	
Kerala	20.66		5.22	1.13		9.86					
Madhya Pradesh	22.09		25.10	81.60	12.71		11.27	0.88	3.53	290.02	
Maharashtra							14			770.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Manipur	11.83	82.55		9,85	1.99	1.58	9.46		2.79	9.30
Meghalaya	22.34				3.67				2.20	
Mizoram	25.00	3.75		15.65	7.06	1.00				87.50
Nagaland			107.85		2.43	1.65	7.31	2,43	4.70	375.00
Orissa	93.07	,		17.55		1.17	15.26	1.16		
Punjab										1442.38
Rajasthan	103,06	٠.	97.59		17.09	52.50	48.74	2.46		158.73 ¹
Sikkim	3.11		0.28						0,20	17. 71
Tripura	43.07	54.17	1.00	1.20	3.70		1.78		1.16	
Uttar Pradesh	181.32		2.11	0.45	52.86	70.58	40.87	17.70	27.72	-848.28
West Bengal										1225.00

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government:

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 1991 against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as revealed in the accounts of that year;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (11) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes approved by the Central Government for upgradation of standards and "Special Problems" mentioned in those columns, incurred in the financial year commencing on the 1st day of April.

1990 :--

TABLE

G	For upgradation of standards relating to											
State	Police	Education	Jail	Tribal	Health	Judicial	District and Revenue	Treasury and Accounts	Training	Special Problems		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				(Rupe	es in lakhs)							
Arunachal Pradesh	77.88	7.22			28.99			8.28				
Assam				91.06	1.57	21.53	4.53	13.05		100.00		
Goa		8.61			10.82	10.53	2.56					
Kerala	49.38		11.91	1.44	4.25	23.20	5.80	0.76				
Madhya Pradesh	59.12		659,64	122.05	5.41	0.21	7.52	0.60		3.48		
Meghalaya	31.81	23.09				2.60	1.24			•••		
Mizoram								4.80				
Nagaland						0.07						
Orissa		221.80		54.58	0.25		1.44					
Rajasthan	13.50	1.1	16.29	7.83	12.52	1.86	7.01	1.00	3.94	56. 99		
Sikkim	0.21			1.09	0.76		(-)0.34					
Tripura	20.91	2.85		1.50	3.57		0.39	0.98	9.29			
Uttar Pradesh	90.48		114.90	1.50	21.84	4.15	41.60	17.29				
West Bengal	609.58	284.76	108.15	99.26	46.66	12.53	7.11	10.53	20.00			

Provided that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess—shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State—in any of the succeeding years or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State in the financial year commencing on the 1st day of April, 1990 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1990.

R. VENKATARAMAN, President

[F. 19(2)/91-L,I] K.L. MOHANPURIA, Addl. Secy.